आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 44 लखनऊ, शनिवार 28 फरवरी 2026 सा 06 मार्च 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी को देंगे ७,१०० करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १ मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करने वाले हैं। राजस्थान और गुजरात के अपने दौरे के बाद, प्रधानमंत्री २८ फरवरी को रात करीब ६ बजे चेन्नई पहुंचेंगे। सोमवार सुबह करीब ११:४५ बजे, प्रधानमंत्री पुडुचेरी में २,७०० करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और देश को समर्पित करेंगे। इस इवेंट के दौरान वे एक पब्लिक गैदरिंग को भी एड्रेस करेंगे। एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थकेयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करना है। **PM** ई–बस सेवा इनिशिएटिव के तहत, वे नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, **CITIIS** स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज और कई सीवरेज और वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कराईकल में डॉ. एपीजे

अब्दुल कलाम ब्लॉक और गंगा हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। वे **JIPMER** में मॉडर्न रीजनल कैंसर सेंटर और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में नई बिल्डिंग्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस दिन की एक खास बात ७५० एकड़ के करासुर–सेदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट को देश को समर्पित करना होगा। इस एस्टेट में एक फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, **IT** पार्क, **IIT** मद्रास का एक रिसर्च सेंटर और **JIPMER** की एडवांस्ड हेल्थकेयर सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पीने के पानी के अपग्रेड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ४१ ग्रामीण सड़कों के निर्माण, हेरिटेज टाउन डेवलपमेंट, **MISHTI** स्कीम के तहत मैंग्रोव रेस्टोरेशन, और पानी, सफाई और बिजली के खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे। पुडुचेरी में अपने काम पूरे करने के बाद, प्रधानमंत्री मदुरै जाएंगे। दोपहर करीब ३ बजे, वह ४,४०० करोड़ रुपये से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह **NH** ३३२। के मरक्कनम से पुडुचेरी सेक्शन और **NH** ८७ के परमकुडी से रामनाथपुरम सेक्शन के चार–लेन कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास करेंगे। रिलीज के मुताबिक, इन हाईवे से यात्रा का समय काफी कम होने और कनेक्टिविटी बढ़ने और इलाके में आर्थिक विकास को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

NCERT Controvery: सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन, BJP MP बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा ८ की एनसीईआरटी किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' नामक चौप्टर शामिल किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीआरटी के डायरेक्टर डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि इस विवादित कंटेंट को तैयार करने वालों के खिलाफ अवमानना या अन्य कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। बीजेपी सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। भले ही एनसीईआरटी ने इस चौप्टर के लिए माफी मांग ली है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ज यमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कक्षा ८ की उस किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बेंच ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश को नजरअंदाज करने या किसी भी तरह से बाईपास करने की कोशिश को न्याय के काम में सीधा दखल और कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को आदेश दिया है कि वह उस 'टीचिंग–लर्निंग मटीरियल्स कमेटी' की पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर रखे जिसने इस चौप्टर को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने चौप्टर बनाने वाली टीम के सभी सदस्यों के नाम, उनकी पढ़ाई–लिखाई और उनके अनुभव का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आज ज्यूडिशियरी खून से लथपथ है और कोई भी कुछ भी

कह सकता है।' सीजेआई के मुताबिक, इंटरनेट और दुकानों पर ऐसा मटीरियल उपलब्ध कराना एक सोची–समझी साजिश है, ताकि पूरी शिक्षा व्यवस्था के जरिए समाज में गलत संदेश जाए। उन्होंने इसे भारतीय न्यायपालिका की छवि खराब करने की एक गहरी और सुनियोजित साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल इस कदम से बेहद गुस्से में है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले के दोषियों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि बाजार में मौजूद ऐसी सभी किताबों को तुरंत वापस लिया जाए। बार काउंसिल के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख का समर्थन किया है और इसे संस्थान की गरिमा बचाने के लिए जरूरी बताया है।

भाजपा वोट काटने की साजिशों के सहारे सत्ता में रहना चाहती हैः अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने को 'वोटबंदी अभियान' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनाधार खो चुकी है और अब वोट काटने की साजिशों के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब सरकार वोटबंदी का अभियान चला रही है। पहले मुसलमानों को कागजों के नाम पर परेशान किया जाता था, अब हिंदुओं को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब वोट के आधार पर नागरिकता तय की जाएगी और लोगों को उनके खेत, जमीन और मकान से बेदखल किया जाएगा? सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब सुभाष चंद्र बोस और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के परिजनों तक को नकार दिया गया तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। सपा प्रमुख ने आशंका जताई कि वोटर कार्ड को लेकर पैदा की जा रही अनिश्चितता से लोग अपने अधिकार, विरासत और संपत्ति को लेकर भय और तनाव में रहेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कागजों के आधार पर पहले वोटर सूची तैयार हुई, उन्हीं दस्तावेजों के रहते अब त्रुटियां कैसे सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि आयोग की गलती है तो सुधार के लिए जनता को क्यों दौड़ाया जा रहा है और क्या गारंटी है कि आगे फिर त्रुटि नहीं होगी? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपनी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और कथित धोखेबाजी के कारण जनाधार खो दिया है, इसलिए अब वह धांधली के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के तथाकथित 'पन्ना प्रमुख' भी जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) वोट काटने की साजिश बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल अधिकारियों से अपील की कि एक भी सही वोट न कटने पाए और एक भी झूठा वोट न जुड़ने पाए। उन्होंने प्रयागराज में नजूल भूमि पर अवैध कब्जों का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाई बाउंड्री खड़ी कर कब्जा कर रहे हैं, जिसे न लखनऊ का बुलडोजर देख पा रहा है, न दिल्ली के ड्रोन। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग विदेश दौरे पर इसलिए गए हैं ताकि बाद में कह सकें कि जब कब्जा हुआ तब वे देश में नहीं थे। उन्होंने निवेश समझौतों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए के एमओयू दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत हवाई अड्डों की तरह 'हवा–हवाई' साबित हुई। उन्होंने व्यंग्य करते हुए पूछा कि विदेश में विकास मॉडल देखने वाले क्या प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को भी याद रखते हैं।

योगी सरकार ने साइन किया २०० करोड़ का एमओयू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आधुनिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए २०० करोड़ रुपये के निवेश हेतु एक जर्मन रेल अवसंरचना कंपनी के साथ बृहस्पतिवार को समझौते की घोषणा की। बृहस्पतिवार शाम यहां जारी बयान के अनुसार, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी में कंपनी के विनिर्माण संयंत्र के दौरे में रेलवन जीएमबीएच के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।बयान के अनुसार, यह कदम राज्य में आधुनिक अवसंरचना विकसित करने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ष्टिकोण के अनुरूप है। मौर्य के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने उन्नत रेल पटरी प्रौद्योगिकियों और आधुनिक कंक्रीट स्लीपर विनिर्माण प्रणालियों का निरीक्षण किया। बयान में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल ने उत्पादन प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रिया को समझने के लिए कंपनी के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

सम्पादकीय

ट्रंप प्रशासन की अस्थिर नीतियां और भारत के सामने सवालः समझौते की ललक या देशहित की चिंता?

अमेरिका ने अब भारत से सौर ऊर्जा से संबंधित पाट–पुर्जों के आयात पर १२६ प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इसे भारत के फूलते–फलते सौर उद्योग पर घातक प्रहार समझा गया है। ड नल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उस समय उठाया, जब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ व र के स्वरूप को लेकर अनिश्चय है। ट्रंप ने जिस कानून के तहत दंडात्मक आयात शुल्क लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ा ठहरा दिया। उसके बाद ट्रंप ने दूसरे कानून के तहत सभी देशों पर दस फीसदी टैरिफ लगाया। बाद में कहा गया कि वे इसे १५ फीसदी तक ले जाएंगे। अब बताया गया है कि आम टैरिफ १० फीसदी रहेगा और ट्रंप बाकी पांच फीसदी का इस्तेमाल विभिन्न देशों के रुख के हिसाब से करेंगे। इस बीच अलग–अलग उत्पादों (मसलन स्टील) पर लगाए गए शुल्क जारी रहेंगे और नए शुल्क भी ट्रंप लगाते रहेंगे, जैसाकि अब उन्होंने सौर ऊर्जा से संबंधित पाट–पुर्जों पर लगाया है। ऐसे में भारत सहित हर देश के सामने यह प्रश्न है कि ट्रंप प्रशासन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का क्या औचित्य है? किसी समझौते के तहत हुई लेनदेन से देश के अधिकांश उद्योगों और अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों को लाभ ना हो रहा हो, तो वैसा समझौता करने की ललक क्यों दिखाई जानी चाहिए? मुद्दा यह भी है कि इस दौर में अमेरिका के साथ हुए समझौते के टिकाऊपन पर हमेशा ट्रंप के मूड की तलवार लटकी रहती है। फिर अमेरिका के भीतर स्थितियां अस्थिर हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं, उस पर वहां राजनीतिक आम सहमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय जाहिर हुआ है कि शासन की सभी संस्थाओं के बीच उन कदमों की वैधानिकता पर आम समझ का अभाव है। इसलिए भारत सरकार को ताजा स्थितियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी भी समय है कि वह पहले इस बारे में देश को भरोसे में ले और राजनीतिक आम सहमति तैयार करे। वरना, समझौते के प्रति उसके उत्साह पर सवाल उठते रहेंगे। उसे याद रखना चाहिए कि ट्रंप के हर मूडी एक्शन के साथ ऐसे सवाल और संगीन होते जाएंगे।

सर्वाइकल कैंसर से बचाने को कल से लगेगी एचपीवी वैक्सीन

लखनऊ। प्रदेश में सर्वाइकल (गर्भाशय) कैंसर की रोकथाम के लिए आज से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के तहत प्रदेश की लगभग ४६ लाख किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १४ वर्ष की आयु

की किशोरियों को गार्डासिल–४ वैक्सीन की सिंगल डोज निःशुल्क दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राजधानी लखनऊ में इसका शुभारंभ करेंगे। यह अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका शनिवार को प्रधानमंत्री अजमेर से शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और उसी दिन अपने–अपने स्तर पर प्रदेश में टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. अरूण कुमार अरूण के अनुसार यह टीका सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध रहेगा। अभियान तीन माह तक प्रतिदिन संचालित होगा, इसके बाद नियमित टीकाकरण दिवसों पर भी यह वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति और आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। टीकाकरण का विवरण यू–विन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। केजीएमयू की गाइनकोल जिक ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. निशा सिंह के अनुसार महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर (२२.८६ प्रतिशत) का बड़ा हिस्सा है और यह एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसकी रोकथाम वैक्सीन से संभव है। उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया। केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के प्रो. विवेक कुमार ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन खाली पेट न लगवाएं। टीका १४ से १५ वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को ही दिया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार, गर्भवती, एलर्जी प्रवृत्ति वाली या पहले एचपीवी वैक्सीन लगवा चुकी किशोरियां यह टीका न लगवाएं।

एआई इम्पैक्ट समिट पर बदले अखिलेश यादव के सुर? अब भाजपा की सुरक्षा को बताया 'पूरी विफलता'

लखनऊ। हाल ही में संपन्न हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आईवाईसी के 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के सहयोगी अखिलेश यादव ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथित सुरक्षा विफलता की कड़ी आलोचना की। यादव ने कहा कि भाजपा ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पहलों के लिए कोई बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया है। संवाददाताओं से बात करते हुए यादव ने कहा कि सबसे पहले तो, भाजपा सरकार के शासन में हमेशा सुरक्षा में चूक होती रही है, और एआई शिखर सम्मेलन पर पहले दिन से ही सवाल उठाए गए थे। यह पूरी तरह से भाजपा की सुरक्षा विफलता है। आपने एआई के लिए कोई बुनियादी ढांचा या बुनियादी संरचना तैयार नहीं की है। जब आप ऐसी चीजें दिखाते हैं जो भारतीय नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग नाराज होंगे। विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, ष्यह एक

लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह एक तानाशाही है। यादव ने भाजपा प्रशासन के शासन संबंधी ज्ञान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारी सरकार आईपी फाइल जमा कर रही है, लेकिन सरकार में कुछ लोगों से पूछिए, उन्हें आईपी का पूरा नाम ही नहीं पता। इससे पहले २१ फरवरी को यादव ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे देश को 'शर्मनाक' महसूस हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को भारत मंडपम में विदेशी प्रतिनिधियों के सामने ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारे बीच आंतरिक मतभेद हो सकते हैंय पूरा देश जानता है कि भाजपा झूठ बोलती है। लेकिन, उन्हें विदेशी प्रतिनिधियों और विश्व प्रतिनिधियों के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी हो। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन २० फरवरी को शिखर सम्मेलन स्थल के अंदर हुआ, जहां समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'समझौता' करने का आरोप लगाया और कहा कि एआई कार्यक्रम में भारत की पहचान को धूमिल किया गया है।

बीएसआईपी ने विज्ञान को आमजन तक पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की

लखनऊ। बीरबल साहनी पुराविज्ञान (बीएसआईपी) ने विज्ञान को आमजन तक पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की है। संस्थान ने साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम श्शकहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगेश्श की शुरुआत की है। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर बीएसआईपी अ डिटोरियम में किया गया। डॉ. केके सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम तीन मार्च से प्रत्येक मंगलवार दोपहर ३ से ४ बजे तक ८६.६ मेगाहटर्ज पर प्रसारित होगा। श्रोता इसे 'केजीएमयू गूंज' मोबाइल ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी सुन सकेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. महेश जी ठक्कर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और समाज के बीच की दूरी को कम करना है। इसमें सामूहिक विलुप्ति, डायनासोर युग, जलवायु परिवर्तन, उल्कापिंडीय टक्करों और मानव विकास जैसे जटिल विषयों को सहज शैली में प्रस्तुत किया

जाएगा। कार्यक्रम का निर्माण बीएसआईपी और रेडियो केजीएमयू गूंज के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इस अवसर पर डॉ. अरविंद माथुर, डॉ. अनुपम शर्मा, डॉ. निमिष कपूर तथा स्टेशन मैनेजर शालिनी गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से धरती के इतिहास, जीवाश्मों, जलवायु परिवर्तन और मानव विकास जैसे विषयों को सरल एवं रोचक भाषा में श्रोताओं तक पहुंचाया जाएगा। वैज्ञानिक स्वयं अपने शोध और खोज की कहानियां साझा करेंगे, ताकि विज्ञान किताबों से निकलकर सीधे समाज से जुड़ सके।

होली पर डॉक्टरों को झटका, स्वास्थ्य विभाग ने रद्द की संविदा भर्ती

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की उम्मीद लगाए बैठे २२५ एमबीबीएस अभ्यर्थियों को होली से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध (संविदा) के आधार पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को अचानक निरस्त कर दिया। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से १६ से २१ जनवरी के बीच एमबीबीएस डॉक्टरों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद २२५ डॉक्टरों ने विभिन्न जनपदों में रिक्त पदों के अनुसार सीटें लॉक कर दी थीं। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि नियुक्ति पत्र जल्द जारी होंगे, लेकिन २६ फरवरी को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। भर्ती रद्द होने से अभ्यर्थियों में रोष है। उनका कहना है कि लंबी प्रक्रिया पूरी करने और सीट लॉक करने के बाद अचानक लिया गया फैसला समझ से परे है। कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट कारण बताने की मांग की है। उधर, महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरूण ने कहा कि अनुबंध के आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। २४१ पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसका विज्ञापन निकाला गया है। इससे अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी।

नवदीप रिणवा ने अलीगढ़ में एसआईआर के कार्यों की समीक्षा की

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को अलीगढ़ में एसआईआर के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर है तो फार्म–७ भरकर स्वेच्छा से उसे कटवा लें। यह एक दण्डनीय अपराध है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मतदाता का होगा। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को भी सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अलीगढ़ में विधान सभा क्षेत्र कोल के सन्त फिदेलिस स्कूल के सुनवाई केन्द्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों

को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। साथ ही अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सीईओ ने युवाओं और महिलाओं से कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह आवश्यक साक्ष्य सहित फार्म–६ भरकर ६ मार्च तक अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें, जिससे उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। एसआईआर के बाद भी नये मतदाता तो बनेंगे, परन्तु उनका रिकॉर्ड एसआईआर के तहत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में इस मौके को न गवाएं। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलो के साथ भी बैठक कर कहा कि वह अधिक से अधिक मतदाता बनवाने में सहयोग करें।

सीएम के सलाहकार पद पर अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ा, २८ फरवरी २०२७ तक रहेंगे तैनात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने हेतु सृजित अस्थायी निःसंवर्गीय पद पर तैनात सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब वे १ मार्च २०२६ से २८ फरवरी २०२७ तक सलाहकार, मुख्यमंत्री के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे। नियुक्ति अनुभाग–१, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पद मूल रूप से कार्यालय ज्ञाप संख्या १/२१४८०६/२०२२, दिनांक १६ सितंबर २०२२ के माध्यम से सृजित किया गया था। इसकी निरंतरता अंतिम बार १ मार्च २०२५ से २८ फरवरी २०२६ तक बढ़ाई गई थी। अब शासन ने पुनः इसकी अवधि में एक वर्ष का विस्तार कर दिया है। आदेश में उल्लेख है कि उक्त पद पर श्री अवस्थी को यथावत तैनात रखने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल द्वारा प्रदान की गई है। यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या E–५–२०५–X–२०२५–२६, दिनांक २० फरवरी २०२६ के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में

जारी किया गया है। गौरतलब है कि यह पद अस्थायी एवं निःसंवर्गीय है, जिसे मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से सृजित किया गया था। शासन के इस निर्णय से प्रशासनिक स्तर पर निरंतरता बनाए रखने की मंशा स्पष्ट होती है।

गुमशुदगी का नाटक, घर से निकली लाशः बेटे ने रची पिता की हत्या की साजिश

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके आशियाना में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। प्रतिष्ठित वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की हत्या उनके ही इकलौते बेटे अक्षत ने कर दी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने न सिर्फ शव के टुकड़े किए, बल्कि उसे छिपाने की साजिश भी रची। घटना २० फरवरी की सुबह करीब ४:३० बजे की बताई जा रही है। पिता मानवेंद्र सिंह और ग्रेजुएशन कर रहे बेटे अक्षत के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हुई। गुस्से में आकर अक्षत ने दीवार पर टंगी अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उतारी और सीधे उनके माथे पर सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घर की दीवारें खून से लाल हो गईं। इस सनसनीखेज वारदात की गवाह आरोपी की ११वीं कक्षा में पढ़ने वाली बहन भी बनी। आरोपी ने बहन को धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका भी वही हश्र होगा। हत्या के बाद अक्षत ने पेशेवर अपराधी की तरह सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने तीसरी मंजिल से शव को घसीटकर नीचे खाली कमरे में लाया और शरीर के दो हिस्से कर दिए। शव के कुछ हिस्सों को कार में रखकर

करीब २० किलोमीटर दूर सुनसान इलाके सदरौना में फेंक आया। बाकी हिस्से को घर में रखे एक नीले प्लास्टिक ड्रम में भरकर छिपा दिया। कार और कमरे की सफाई कर खून के निशान मिटाने की भी कोशिश की गई। हत्या के तीन दिन बाद आरोपी अक्षत थाने पहुंचा और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह पुलिस के सामने रोता रहा ताकि शक उससे दूर रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि पिता अपने इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि अक्षत रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। पड़ोसियों के अनुसार, अक्षत का व्यवहार पहले से संदिग्ध था। वह अक्सर पिता की बंदूक लेकर घूमता था और उसके पार्ट्स खोलकर साफ करता रहता था। करीब चार महीने पहले घर के गहने चोरी करने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद मोहल्ले के अन्य बच्चे उससे दूरी बनाकर रखते थे। पुलिस की गाड़ियां जब आशियाना स्थित घर के बाहर पहुंचीं तो किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर इतनी भयावह सच्चाई छिपी है। नीले ड्रम से शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। यह घटना न केवल पारिवारिक संबंधों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि युवाओं में बढ़ते आक्रोश और मानसिक तनाव की भी गंभीर तस्वीर पेश करती है।

१०२५ करोड़ की ठगी का आरोपः शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई में फरार, ८६ गिरफ्तार

लखनऊ/प्रयागराज। बहुचर्चित निवेश घोटाले में फंसे **Shine City Group of Companies** के मुख्य प्रबंध निदेशक राशिद नसीम समेत अन्य पर बड़ी कार्रवाई जारी है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने ५००० से अधिक निवेशकों से करीब १०२५ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई, लेकिन न तो प्ल टध्भू–खंड दिए और न ही निवेश की रकम लौटाई। जानकारी के अनुसार वर्ष २०१३ में राशिद नसीम ने रजिस्ट्रार अ फ कंपनीज, कानपुर से शाइन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. का पंजीकरण कराया था। कंपनी में उसके सगे भाई आसिफ नसीम सहित अन्य लोग निदेशक थे। बाद में आरओसी कानपुर, दिल्ली और हरियाणा से ३३ सहायक कंपनियां भी पंजीकृत कराई गईं। कंपनी ने सस्ते प्लॉट, ज्वैलरी और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर बड़े पैमाने पर निवेश कराया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में कार्यालय खोलकर आकर्षक योजनाओं का प्रचार किया गया। समयावधि पूरी होने के बाद निवेशकों को न तो भूखंड मिले और न धनवापसी हुई। इसके बाद कार्यालय बंद कर आरोपी फरार हो गए। निवेशकों की शिकायत पर प्रदेश के विभिन्न थानों में ५५० मुकदमे दर्ज हुए, जिन्हें शासन के आदेश पर अप्रैल २०२१ से **Economic Offences Wing Uttar Pradesh** (ईओडब्ल्यू) को जांच के लिए सौंपा गया। ईओडब्ल्यू की विवेचना में अब तक ८६ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ५२७ मामलों में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए गए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी राशिद नसीम और एक अन्य अभियुक्त अब भी फरार हैं। जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष २०१६ में

राशिद नसीम भारत से नेपाल के रास्ते फरार होकर दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में रह रहा है। उसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू, धारा ८२–८३ सीआरपीसी (कुर्की), लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। उसका पासपोर्ट भी निरस्त कर दिया गया है। राशिद नसीम, आसिफ नसीम व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। लखनऊ स्थित फ्लैट, प्रयागराज स्थित मकान समेत अन्य संपत्तियां ईओडब्ल्यू द्वारा सीज की जा चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा गया है, जो वहां की सरकार के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण को प्रदेश के बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल माना जा रहा है और हजारों निवेशक अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

तिन्नी पसई चावल से बने पापड़–कचरी होली पर स्वाद के साथ सेहत का भी रखेंगे ख्याल

लखनऊ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला समूह के तिन्नी पसई चावल से बने पापड़–कचरी होली पर स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखेंगे। हाथ से बने ये पापड़–कचरी केमिकल मुक्त हैं, इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। विशेष पैकिंग वाले इन पापड़–कचरी की बिक्री २८ फरवरी से सरकारी परिसरों में स्टॉल लगाकर की जाएगी। मिशन के निर्देश पर मां शिवधात्री समूह चिनहट की महिलाओं ने तिन्नी पसई चावल के पापड़ और कचरी तैयार किए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के इस चावल को पसई चावल भी कहते हैं। इसमें आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट का प्राकृतिक स्रोत होता है। ग्लूटेन–मुक्त होने के साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ये चावल शुगर मरीजों के लिए वरदान है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस चावल से बने खाद्य पदार्थ त्योहार के साथ व्रत में भी खाए जाते हैं। समूह की महिलाओं ने आचार, चाट मसाला, पूजन सामग्री आदि भी बनाई है। समूह की अध्यक्ष सुषमा साहू ने बताया कि दो–दो क्विंटल पापड़– कचरी की मांग है। इसमें ५० फीसद तक तैयार करके पैकिंग कर ली है। ये आगरा, दिल्ली और कानपुर

जाएगा। समूह का गोमती नगर के हुसड़िया में अवनि रिटेल स्टोर संचालित है यहां भी बिक्री करेंगे। इसके अलावा २८ फरवरी से सरकारी परिसरों में स्टॉल लगाएंगे। समूह में शामिल १२ महिलाओं को इससे रोजगार मिला है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के करारे जवाब ने पाकिस्तान और उसके तोते ओआईसी को दिखाया आईना, बगलें झाँकने लगा इस्लामाबाद

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई, जब उसने जम्मू–कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन इस बार भारत ने तथ्यों के ऐसे तीर चलाए कि इस्लामाबाद की बयानबाजी हवा हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ६१वें नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने जिस स्पष्टता और ढ़ता से जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान एक "खयाली दुनिया" में जी रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कर्ज के सहारे चल रही हो, वह लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर भाषण दे, यह अपने आप में विडंबना है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से जिस राहत पैकेज की गुहार लगाई, जम्मू–कश्मीर का विकास बजट उससे दोगुना से भी अधिक है। यह तुलना अपने आप में बताती है कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना कठिन लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र

मजबूत हो रहा है। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रिक र्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता ने आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को नकार दिया है। यह वही विचारधारा है जिसे दशकों तक पाकिस्तान ने खुला या छिपा समर्थन दिया। लेकिन अब घाटी के लोग विकास, रोजगार और स्थिरता चाहते हैं और भारत सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) का उल्लेख करते हुए कहा, ''उच्च स्तरीय खंड के दौरान पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा भारत के संदर्भ में की गई टिप्पणियों के बाद भारत अपना जवाब देने का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए बाध्य है। हम इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं।'' उन्होंने साफ कहा कि ऐसे देश से लोकतंत्र पर उपदेश सुनना अटपटा है जहां असैन्य सरकारें शायद ही कभी अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। उन्होंने कहा, ''जम्मू–कश्मीर में दुनिया के जिस सबसे बड़े पुल, चिनाब रेल पुल का पिछले साल उद्घाटन किया गया था, यदि वह फर्जी है तो फिर पाकिस्तान भ्रम या खयाली दुनिया में जी रहा है।'' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को ''तोते की तरह दोहराकर'' ओआईसी केवल यह दर्शाता है कि उसने खुद को एक सदस्य द्वारा कितनी गहराई से प्रभावित होने दिया है। अनुपमा सिंह ने कहा, ''पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार अब ईर्ष्या से भरा हुआ प्रतीत होता है। हम ऐसे दुष्प्रचार को महत्व नहीं देना चाहते लेकिन हम कुछ बिंदु रखेंगे और तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान की कोई भी मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को बदल नहीं सकता कि जम्मू–कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और अपरिवर्तनीय है तथा यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (१९४७) एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है।'' उन्होंने कहा, ''दरअसल, इस क्षेत्र के संबंध में एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से इन क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं, जिस पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है।'' बहरहाल, इस्लामी सहयोग संगठन पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए चाहे जो भी कहे लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इन घिसी–पिटी दलीलों से प्रभावित नहीं होता। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वैश्विक मंचों पर खोखली बयानबाजी से उसकी आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हल नहीं होंगी। बेहतर होगा कि वह अपनी ऊर्जा आतंकवाद के निर्यात की बजाय अपने नागरिकों के भविष्य को सुधारने में लगाए। भारत आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन पर हकीकत का सामना करना होगा। यही सच्चाई है और यही उसकी असली औकात भी।

फाल्गुन मास की मस्ती अपने चरम पर, रंगभरी एकादशी पर भक्तिरस में डूबा देश

मथुरा। फाल्गुन मास की मस्ती अपने चरम पर है और देश के विभिन्न हिस्सों में रंग, अबीर और गुलाल की छटा बिखर गई है। ब्रज क्षेत्र के बरसाना, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन में जहां लट्ठमार होली और पारंपरिक उत्सवों की धूम देखने को मिल रही है वहीं काशी में रंगभरी एकादशी के अवसर पर बाबा के दरबार में रंगों की अनोखी आभा देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ हो रहा है। नंदगांव के हुरियारे परंपरागत वेशभूषा में बरसाना पहुंचे तो अलग ही छटा देखने को मिली। प्रिया कुंड पर उनका स्वागत मिठाई, पकवान और ठंडाई से किया गया। इसके बाद वे लाडली जी मंदिर में दर्शन कर रंगीली गली पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर होली के रसिया गूंज उठे। जैसे ही हुरियारों ने महिलाओं को रिझाने के लिए गीत गाए, हुरियारिनों ने प्रेम भरी लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। पुरुषों ने ढाल से बचाव किया और पूरा वातावरण हंसी ठिठोली से गूंज उठा। हम आपको बता दें कि यूपी प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांटकर हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रमुख स्थलों पर कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं व्यवस्था पर नजर बनाए रहे। श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं की सराहना की। इसी क्रम में मथुरा और वृंदावन में भी होली का रंग चरम पर दिखाई दिया। मंदिरों में ठाकुर जी के संग गुलाल की होली खेली गई। बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों की बौछार ने वातावरण को और भी सुरम्य बना दिया। विदेशी श्रद्धालु भी इस अनूठे उत्सव में शामिल होकर नाचते गाते नजर आए। हम आपको बता दें कि ब्रज में

होली का उत्सव बसंत पंचमी से आरंभ होकर कई सप्ताह तक चलता है, परंतु लट्ठमार होली और रंगभरनी एकादशी इसका विशेष आकर्षण माने जाते हैं। मान्यता है कि द्वापर काल में कान्हा अपने सखाओं के साथ बरसाना आकर राधा और सखियों को चिढ़ाते थे, तब सखियां उन्हें लाठियों से खदेड़ देती थीं। वही परंपरा आज भी जीवंत है। उधर काशी में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व देखा गया। धार्मिक मान्यता है कि विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे और भक्तों ने रंगों से उनका स्वागत किया था। इसी परंपरा के तहत मंदिर परिसर में पुष्प, अबीर और गुलाल से होली खेली गई। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के साथ उत्सव मनाया। हम आपको बता दें कि रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, महादेव और आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। रंग, रस और भक्ति से सराबोर यह पर्व सामाजिक समरसता और प्रेम का संदेश देता है। बरसाना की लाठियों में जहां स्नेह छिपा है, वहीं मथुरा की गलियों में भक्ति का रंग और काशी में आस्था की छटा दिखाई देती है। फाल्गुन का यह उत्सव एक बार फिर देश को रंगों की डोर में बांधता नजर आया। अयोध्या में भी इस अवसर पर साधु संत झूमते नजर आये।

यूट्यूबर का दर्दनाक अंत, ब्रेकअप से टूटी लड़की, पंखे से लटककर दी जान

लखनऊ। २१ साल की पार्ट–टाइम यूट्यूबर बोनू कोमाली ने आत्महत्या कर ली है। कोमाली मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की रहने वाली थीं और पिछले ११ महीनों से हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में अकेले रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थीं। वह यूट्यूब पर अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो शेयर किया करती थीं। पुलिस जांच में सामने आया है कि जान देने से ठीक पहले कोमाली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने कुवैत में रह रही अपनी मां को आखिरी मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, 'आई लव यू मम्मी सो मच, छोटे भाई का ख्याल रखना।' जब मां के फोन करने पर भी कोमाली ने कॉल नहीं उठाया, तो उन्होंने एक दोस्त को घर भेजा। वहां दरवाजा तोड़ने पर कोमाली का शव पंखे से लटका मिला। शुरुआती जांच के अनुसार, कोमाली पिछले तीन साल से एक स फ्टवेयर इंजीनियर के साथ रिश्ते में थीं, जो खुद भी एक यूट्यूबर है। खबर है कि हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके कारण वह काफी तनाव में थीं। पुलिस को पता चला है कि कोमाली ने ६ महीने पहले भी जान देने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस फोन रिक र्ड्स और दोस्तों के बयानों के आधार पर मामले की पूरी जांच कर रही है।

मृतक आश्रितों को मिलेगी तीन माह में नौकरी

लखनऊ। सरकारी विभागों में अनुकंपा में मिलने वाली नौकरी को लेकर बेवजह विलंब किए जाने की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम तीन माह के भीतर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि परिवारों को राहत मिल सके। कार्मिक अनुभाग–२ की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली– १९७४ का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है।

अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस ने जताई नाखुशी, आप ने किया राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा पर पलटवार

नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। दरअसल अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगले साल वहां होने वाले

विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस खुद को सत्ता का प्रबल दावेदार मान रही है। ऐसे में उसे डर है कि केजरीवाल को यदि सहानुभूति का लाभ मिल गया तो आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में लौट सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस को यह भी डर है कि जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए देश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, उसकी काट के लिए केजरीवाल को सामने लाया गया है ताकि वह मोदी पर हमला करके राहुल के मुकाबले बढ़त ले सकें। कहने को आम आदमी पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन की घटक रही है लेकिन उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के रिहा होने से जिस तरह कांग्रेस नेताओं के चेहरे लटक गये हैं उससे सभी हैरत में हैं। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और कई अन्य के बरी होने के बाद कांग्रेस ने आज दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात और पंजाब के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 'नहला–धुलाकर और वाशिंग मशीन से निकालकर' पेश कर रही है ताकि मुख्य विपक्षी दल को कमजोर किया जा सके। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा एक 'इच्छाधारी नाग' है जो सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए अपना रूप बदलती रहती है और इसके लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकती है। पवन खेड़ा ने कहा, ''गुजरात और पंजाब के चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को नहला–धुलाकर और वाशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है क्योंकि भाजपा का असली मकसद कांग्रेस मुक्त भारत है।'' उन्होंने दावा किया कि कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, यही भाजपा का खेल है और इसमें कई खिलाड़ी और अंपायर बिके हुए हैं। दूसरी ओर, पवन खेड़ा के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मैं आपसे पूछता हूं कि केजरीवाल जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया? संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गईं? कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती?' हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने भी टिप्पणी की है कि इस तरह के घटनाक्रम अक्सर राज्यों में चुनावों के साथ मेल खाते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अदालत के फैसले के समय को लेकर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। वहीं जहां तक भाजपा की बात है तो आपको बता दें कि पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि CBI ऊपरी अदालत में जा रही है।

अलीनगर सुनहरा के बेसिक विद्यालय में 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पर नुक्कड़ नाटक, बच्चों को दिए यातायात नियमों के अहम संदेश

लखनऊ। बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन **Mamta HIMC Foundation** द्वारा किया गया, जिसकी समन्वयक **Deepa**

Negi की देखरेख में पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' शीर्षक से प्रस्तुत इस नाटक के माध्यम से बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने, यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने के महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। कलाकारों ने सरल संवाद, प्रभावी अभिनय और रोचक प्रस्तुति के जरिए यह समझाया कि छोटी–सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नाटक में टीम लीडर मनोज के नेतृत्व में कलाकार अफसाना, रजनीकांत सोनकर लंकेश, अरून और मनोज ने प्रभावशाली अभिनय किया। कलाकारों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने तथा मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण नियमों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और सवाल–जवाब सत्र में अपनी जिज्ञासाएं भी साझा कीं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पाण्डेय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का संकल्प है, जिसे हर नागरिक को गंभीरता से अपनाना चाहिए।

बंगला बाजार हत्याकांडः पैथाल जी व शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या में जांच तेज, संदिग्ध महिला की तलाश

लखनऊ। राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित बंगला बाजार में चर्चित पैथाल जी और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। मामले में अब एक संदिग्ध महिला का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। आशियाना थाने के इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के अनुसार, मुख्य आरोपित अक्षत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मंगाई गई है। कॉल रिकॉर्ड मिलने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ लोगों ने अक्षत के एक महिला के संपर्क में होने की जानकारी दी थी। इसी आधार पर पुलिस अब उस महिला की तलाश में जुटी है, ताकि संभावित साजिश के पहलुओं को खंगाला जा सके। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, वैज्ञानिक जांच पर जोर पुलिस उन सभी मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जहां से अक्षत कथित तौर पर वारदात के बाद अपने पिता के हाथ–पैर ठिकाने लगाने गया था। इसके अलावा, घटनास्थल से बरामद असलहा, खोखा, कारतूस और मैगजीन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। विशेषज्ञों

की रिपोर्ट को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे घटना की परिस्थितियों और हथियार के इस्तेमाल को लेकर अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद सबसे पहले अक्षत की बहन कृति मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर यह जानने का प्रयास किया है कि उसने घटनास्थल पर क्या देखा, राइफल कहां पड़ी थी और उस समय अक्षत की स्थिति कैसी थी। माना जा रहा है कि पुलिस ॅति को सरकारी गवाह बनाने पर विचार कर रही है, जिससे अभियोजन पक्ष को मजबूती मिल सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अक्षत ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? पुलिस का कहना है कि हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए।

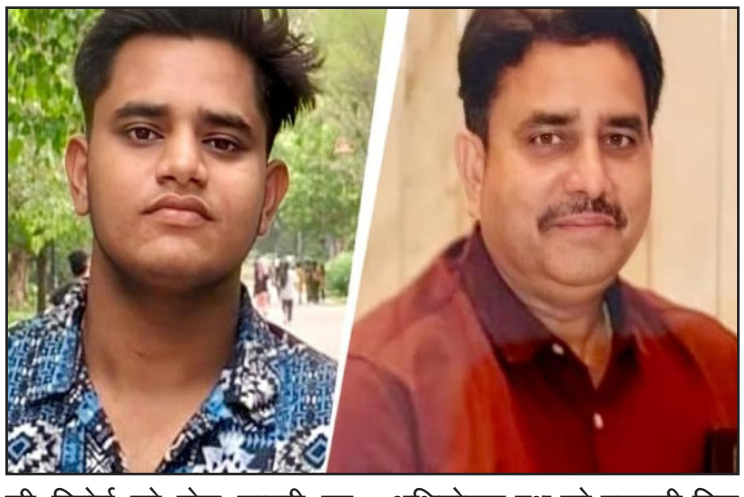

गाजा संकट के बीच मोदी की इजराइल यात्रा पर महबूबा मुफ्ती भड़कीं, कहा- प्रधानमंत्री को नेतन्याहू को गले नहीं लगाना चाहिए था

नई दिल्ली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मेलजोल और गर्मजोशी भरे संवाद पर आपत्ति जताई। अनंतनाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि १.४ अरब से अधिक लोगों के देश के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को अपने हर कूटनीतिक कदम के संदेश और प्रभाव के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। उनका कहना था कि गाजा की मौजूदा स्थिति ने वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है और ऐसे समय में किसी भी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग संकेत दे सकता है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि गाजा संघर्ष के दौरान नागरिकों की मौतों के लिए नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें "अंतरराष्ट्रीय अपराधी" तक करार दिया और दावा किया कि कुछ देशों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना हो सकती है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष देश या कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका संकेत अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के मुद्दों की ओर था। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को ऐसे नेताओं

को गले लगाते हुए नहीं देखा जाना चाहिए।" मुफ्ती ने यह भी जोड़ा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक मामलों में नैतिक रुख अपनाया है और शांति व न्याय के पक्ष में अपनी स्पष्ट स्थिति रखी है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति को उसी परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से अपनी कूटनीतिक नीति की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति को उसके घोषित सिद्धांतों शांति, न्याय और मानवाधिकार के अनुरूप प्रतिबिंबित होना चाहिए।

न्यायपालिका पर 'विवादास्पद' अध्यायः सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, केंद्र को फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान ('ocial Science) की उस किताब पर पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' नामक एक अध्याय शामिल था। न्यायालय ने इस मामले को 'गहरी साजिश' करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो लोग 'ज्यूडिशियरी करप्शन' पर चौप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल हैं, वे UGC या किसी भी मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे। केंद्र ने बिना शर्त माफी भी मांगी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'एक सुओ मोटो केस में, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं।' इस बीच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पलटवार करते हुए कहा, 'मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा है। इसमें माफी का एक भी शब्द नहीं है।' जब SG मेहता ने कहा कि ३२ किताबें बिक चुकी थीं लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, तो CJI ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया

कदम था। CJI ने कहा, 'पूरी टीचिंग कम्युनिटी को बताया जाएगा कि इंडियन ज्यूडिशियरी करप्ट है और केस पेंडिंग हैं... फिर स्टूडेंट्स, और फिर पेरेंट्स। यह एक गहरी साजिश है।' NCERT की सोशल साइंस बुक के 'ज्यूडिशियल करप्शन' चौप्टर में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत बड़ा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। नई बुक में कहा गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को बल्कि कोर्ट के बाहर उनके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है। चौप्टर में लिखा है, 'लोग ज्यूडिशियरी के अलग–अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, यह न्याय तक पहुंच की समस्या को और खराब कर सकता है। इसलिए, स्टेट और यूनियन लेवल पर ज्यूडिशियल सिस्टम में भरोसा बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है, और जहां भी करप्शन के मामले सामने आएं, उनके खिलाफ तेज और पक्के एक्शन लिए जाएं।' किताब में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की अनुमानित संख्या ८१,०००, हाई कोर्ट में ६२.४० लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबअ र्डिनेट कोर्ट में ४.७० करोड़ बताई गई है।

वायनाड भूस्खलन पीड़ितों से बोले राहुल गांधी, कांग्रेस बनवाकर देगी १०० नए घर

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को साल २०२४ में आए भीषण भूस्खलन के पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत योजना की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी की ओर से बनाए जाने वाले १०० घरों का शिलान्यास किया। कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे ये घर १,१०० स्क्वायर फीट के होंगे, जिनमें से हर घर के लिए ८ सेंट जमीन दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनका पूरा परिवार उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया है। राहुल गांधी ने पीड़ितों की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, 'आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपना हौसला और दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं खोई।' उन्होंने घर बनाने की प्रक्रिया में हुई देरी का भी जिक्र किया और बताया कि जमीन की परमिशन और अन्य कागजी कार्रवाई के कारण समय लगा, लेकिन अब यह काम जल्द पूरा होगा। उन्होंने इस पहल को पीड़ितों के लिए प्यार और साथ का एक संदेश बताया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीड़ितों का दुख साझा करते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों की मुश्किलें देखी हैं जिन्होंने अपने परिजनों और खेतों को खो दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर इसे 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की थी और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था।

प्रियंका ने कहा कि हादसे के वक्त वह सांसद नहीं थीं, लेकिन अब वह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बेटी और बहन की तरह हैं। उन्होंने इस बात की भी खुशी जताई कि सभी राजनीतिक दलों ने पुनर्वास के काम में मदद की है। कार्यक्रम के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने उन ४० दुकानदारों को ५–५ लाख रुपये की आर्थिक मदद भी बांटी, जिनकी दुकानें भूस्खलन में तबाह हो गई थीं। इस अवसर पर कांग्रेस और यूडीएफ के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज। एक अहम घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी। कोर्ट के आदेश में मामले में अगली सुनवाई तक जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। राहत की मांग वाली याचिका चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच दायर की गई थी, और बेंच ने अधिकारियों को शंकराचार्य के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर करीब ३.४५ बजे संत की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। उनके शिष्य संजय पांडे ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने रोजाना के धार्मिक काम जारी रखे और हमेशा की तरह अपनी रोज की पूजा–पाठ की। मठ में बड़ी संख्या

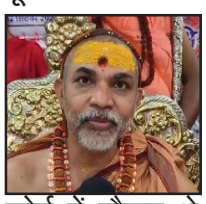

में मीडियाकर्मी मौजूद थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। जिन्होंने झूठी कहानी बनाई है, वे बेनकाब हो रहे हैं। जैसे–जैसे लोगों को इस मनगढ़ंत मामले के बारे में पता चलेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। मेडिकल जांच रिपोर्ट से जुड़े दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक मेडिकल रिपोर्ट हमारी संलिप्तता कैसे साबित कर सकती है? कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में गलत काम साबित हुआ है। यह किसी का बयान हो सकता है, लेकिन इतने दिनों बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का क्या मतलब है?ष उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ भी होता, तो इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा, ष्जो बच्चा कभी हमारे पास नहीं आया, उसे आसानी से हमारे नाम से नहीं जोड़ा जा सकता।

बाराबंकी में ३०० मीटर सड़क निर्माण अटकारू आदेशों के बावजूद कार्रवाई नहीं, नई बस्ती गुग्गौर में जलभराव से लोग परेशान

लखनऊ/बाराबंकी। जनपद के कुर्सी रोड स्थित ग्राम गुग्गौर की नई बस्ती में लगभग ३०० मीटर सड़क एवं नाली निर्माण का मामला पिछले पांच वर्षों से लंबित बताया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार लगातार प्रार्थना पत्र देने और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। बताया गया कि बस्ती के प्रतिनिधि द्वारा मामला माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ में जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा ६६ के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद २ जुलाई २०२५ को जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) बाराबंकी ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) निंदुरा को क्षेत्र पंचायत समिति के माध्यम से कुर्सी राजमार्ग की ऊंचाई तक सड़क एवं नाली निर्माण कराने के निर्देश जारी किए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ। उनका कहना है कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं मंत्रियों द्वारा भी जिलाधिकारी बाराबंकी को लिखित रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। २३ फरवरी २०२५ को जिलाधिकारी स्तर से भी बीडीओ निंदुरा को निर्माण कार्य कराने के आदेश जारी होने की जानकारी दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। नई बस्ती के निवासियों के अनुसार हर वर्ष बरसात के दौरान लगभग दो फीट तक जलभराव हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। क्षेत्रवासियों ने

संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि वर्षों से लंबित इस समस्या का समाधान हो सके। यह मामला प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और क्रियान्वयन की स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस पर क्या रुख अपनाता है और क्षेत्रवासियों को राहत कब तक मिलती है।

शिक्षक आत्महत्या प्रकरणः देवरिया की बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबित, विभागीय जांच शुरू

देवरिया/लखनऊ। शिक्षक आत्महत्या प्रकरण और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में देवरिया की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन ने उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, १९९९ के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। मामला २२ फरवरी २०२६ को प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा २३ फरवरी २०२६ को गठित जांच समिति की आख्या शासन को भेजी गई थी। परीक्षण के दौरान पाया गया कि मा. उच्च न्यायालय में गोचित रिट याचिका । संख्या–७४४६/२०२३ में १३ फरवरी २०२५ को पारित आदेश के अनुपालन में बीएसए कार्यालय द्वारा लगभग एक वर्ष तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जांच में प्रथम दृष्टया यह माना गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लापरवाही

बरती गई तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और अनियमितता पाई गई। इसी आधार पर राज्यपाल की स्वीकृति से उन्हें नियम–४ के तहत निलंबित करते हुए नियम–७ के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। विभागीय जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती श्रीवास्तव को शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) देय होगा। अन्य भत्तों का भुगतान नियमानुसार एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर किया जाएगा, जिसमें यह घोषित करना होगा कि वे किसी अन्य सेवायोजन या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। शासन के इस कदम को शिक्षक आत्महत्या प्रकरण में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

बांकेगंज और धौरहरा ब्लॉक ने रचा रिकॉर्ड, इंडिकेटर्स के सैचुरेशन में प्रदेश में बनाई अलग पहचान

लखीमपुर खीरी। विकास की दौड़ में लखीमपुर खीरी ने ऐसा परचम लहराया कि राष्ट्रीय पटल पर उसकी गूंज सुनाई दी। जुलाई से सितंबर २०२४ के बीच चले संपूर्णता अभियान में जिले के बांकेगंज और धौरहरा ब्लॉक ने प्रदर्शन की नई इबारत लिख दी। उत्कृष्ट कार्य के लिए नीति आयोग ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। बांकेगंज ब्लॉक ने 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन', 'एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज' और 'एस्पिरेशनल ब्ल क्स प्रोग्राम के तहत सोशल डेवलपमेंट' थीम में तीन प्रमुख इंडिकेटर्स पर शत–प्रतिशत सैचुरेशन हासिल कर प्रशासनिक चुस्ती का परिचय दिया। जमीनी निगरानी, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और तय समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने की रणनीति ने ब्लॉक को मॉडल बना दिया। धौरहरा ब्लॉक ने तो रफ्तार को और तेज कर दिया। यहां छह इंडिकेटर्स पर सैचुरेशन हासिल कर विकास के पैमाने पर नई लकीर खींच दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, पोषण सुधार की ठोस

पहल और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधी पहुंच ने नतीजे को असरदार बनाया। संपूर्णता अभियान के तहत किए गए इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और टीमवर्क साथ हो, तो लक्ष्य सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, जमीन पर उतरते हैं। जिले में इस उपलब्धि को विकास की नई उड़ान के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का माहौल खास रहा। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सीडीओ अभिषेक कुमार की मौजूदगी में बांकेगंज के बीडीओ ऋषिकांत अहिरवार और धौरहरा के तत्कालीन बीडीओ सुमित कुमार सिंह (वर्तमान में बीडीओ फूलबेहड़) को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डीएम ने साफ कहा कि यह सम्मान किसी एक अधिकारी का नहीं, बल्कि उस पूरी टीम का है जिसने लक्ष्य को मिशन बना लिया। उन्होंने अधि ाकारियों से कहा कि संपूर्णता अभियान ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्लानिंग सटीक हो, मॉनिटरिंग लगातार हो और टीम में समन्वय हो, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी तय समय में हासिल किए जा सकते हैं। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार की प्रशंसा करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और विभागों के बीच समन्वय ने अभियान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उनकी मेहनत और दृष्टिकोण ने टीम को हमेशा प्रेरित रखा।

मां और दो बेटियों ने खाया जहर, दो की मौत, एक गंभीर

लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र के गांव काकोरी निवासी विजेंद्र कुमार की पत्नी ५० वर्षीय फूल कुमारी, पुत्री कंचन देवी २५, पुत्री निमिषा १६ ने जहर खा

लिया। गंभीर अवस्था में परिजन तीनों को लेकर गोला सीएचसी आए, जहां फूल कुमारी और निमिषा को ड क्टरों मृत घोषित कर दिया। कंचन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पिता और भाई ने बताया कि विजेंद्र के बड़े पुत्र पवन कुमार की ४ दिसंबर को पूरनपुर मार्ग स्थित कजरी के पास सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। जिसे लेकर परिवार के लोग डिप्रेशन में थे। घर पर घटना के वक्त मृतक पुत्र पवन कुमार की पत्नी उसके दो बच्चे और मां–बेटियां थे। विजेंद्र और उनका छोटा पुत्र आशीष अपने काम पर भरिगवां गए थे। भरिगवां में विजेंद्र कुमार का आटा चक्की कारखाना है।

कानपुर में संगठित लूट का खुलासा, पुलिस ने छह कथित बदमाशों को किया गिरफ्तार

कानपुर। कानपुर पुलिस ने छह कथित बदमाशों को गिरफ्तार कर एक संगठित लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छह में से दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उनके पैर में गोली लगी है। उसने बताया कि ये गिरफ्तारियां श्याम नगर पुलिस चौकी के पास हुई एक लूट से जुड़ी हैं, जो करीब दो हफ्ते पहले हुई थी। पुलिस ने बताया कि १५ फरवरी को यशोदा नगर निवासी मोहम्मद वासिद और जाजमऊ निवासी अरशद पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कथित तौर पर हमला किया और उनसे आठ लाख रुपये की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस मामले में अब्दुल रहमान, शुभान खान, लारेब सिद्दीकी और मोहम्मद जीशान सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे लूटी गई धनराशि का एक हिस्सा पुलिस द्वारा बरामद किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में दिन में हुई मुठभेड़ में दो अन्य आरोपियों बेकनगंज निवासी मोहम्मद यासीन और मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि पुलिस टीम बृहस्पतिवार देर रात वाहनों की नियमित जांच कर रही थीं तभी रुकने का इशारा करने पर दो मोटरसाइकिल सवार भागने की कोशिश करने लगे। डीसीपी ने कहा, "संदिग्धों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दोनों आरोपियों यासीन और मुजाहिद के पैर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।श्श गुप्ता ने दोनों को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के मुताबिक संगठित गिरोह के सदस्यों ने वासिद और अरशद से लूटपाट करने से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। आरोप है कि गिरोह के दो सदस्यों ने नकदी लाने–ले जाने पर नजर रखी और अपने साथियों को जानकारी दी, जिन्होंने लूट को अंजाम दिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पीड़ित ने शुरू में किसी भी लूट से इनकार किया था और घटना को बाइक सवारों से टक्कर के बाद एक सड़क हादसा बताया था। हालांकि, बाद में सीसीटीवी फुटेज से यह निश्चित हो गया कि लूट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। लाल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जांच के दौरान, पुलिस को जाजमऊ निवासी महफूज नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिली, जो कबाड़ और चमड़े का कारोबार करता है। उन्होंने बताया कि लूटपाट के शिकार कथित तौर पर उसी के लिए नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि घटना वाले दिन एक बैंक खाते से करीब ३.२ करोड़ रुपये निकाले गए, जिसमें से करीब २५ लाख रुपये लूट के समय ले जाए जा रहे थे। लाल ने बताया, ष्हमने संदिग्ध ा ऑपरेटर से जुड़े १४ बैंक खातों का पता लगाया है, जिसमें पिछले ढाई साल में एक ही बैंक के जरिए करीब ८५० करोड़ रुपये की लेनदेन हुए हैं।' उन्होंने बताया कि १२ बैंकों के ६८ खातों की जांच से करीब १,६०० करोड़ रुपये नकदी निकाले जाने की जानकारी मिली है, जिससे कर चोरी और गैर–कानूनी वित्तीय गतिविधि का शक पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों की आवाजाही दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके, कश्मीर और नेपाल में होने की जानकारी मिली है, जिससे एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का संकेत मिलता है। लाल ने कहा, 'हमने संदिग्ध हवाला कारोबार की आगे की जांच के लिए आयकर विभाग, माल एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने का फैसला किया है।'' उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि लूट के दौरान जिन दो लोगों पर हमला हुआ, वे सिर्फ नकद ले जा रहे थे और साजिश का हिस्सा नहीं थे। पुलिस आयुक्ध्त ने गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली टीम को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

मुंडन कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर फटने से लगी आग

लखीमपुर खीरी। थाना भीरा अंतर्गत मटेहिया गांव में शुक्रवार को एक गैस सिलेंडर फटने से दो घरों में आग लग गई। यह हादसा एक मुंडन कार्यक्रम के दौरान हुआ, जब खाना बनाने के लिए रखे तीन सिलेंडरों में से एक में आग लग गई। आग की चपेट में आने से दो घरों का सामान जल गया, हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।आग से बिंद्रा प्रसाद पुत्र बिहारी और जसपाल पुत्र छोटेलाल के छप्परों को नुकसान पहुंचा और उनका समस्त घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। थानाध्यक्ष भीरा रोहित दुबे ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी ने किया साप्ताहिक परेड का निरीक्षण

लखीमपुर खीरी। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डा० ख्याति गर्ग द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन खीरी के परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिसकर्मियों की परेड ड्रिल करायी गई। परेड में पुलिस लाइन का पुलिस बल तथा विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त समस्त पुलिसकर्मी एवं प्रशिक्षु रिक्रूट आरक्षी सम्मिलित हुए। निरीक्षण के पश्चात महोदया द्वारा परेड में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को साफ–सुथरी एवं स्वच्छ वर्दी धारण करने तथा नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित समस्त शाखाओध् कार्यालयों का भ्रमण कर अभिलेखों का अवलोकन करते हुए प्रतिसार निरीक्षक व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

समस्त अभिलेखों के व्यवस्थित रख–रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महोदया द्वारा पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर मेस का निरीक्षण कर भोजनालयो में समस्त मूल भूत सुबिधाओं सहित भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया।

टी.ई.टी. अनिवार्यता से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग, बीएसए कार्यालय पर धरना

लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–२००६ के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की अनिवार्यता को लेकर जनपद के शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है। २७ जुलाई २०११ से लागू किया गया था। अधिनियम के अनुसार इस तिथि के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया, रहने अथवा पदोन्नति के लिए टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे शिक्षकों ने "पूर्व प्रभाव से लागू किया गया अन्यायपूर्ण निर्णय" बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। धरने में शामिल शिक्षकों ने बताया कि देशभर में टीचर्स फेडरेशन अ फ इंडिया के बैनर तले आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के उपरांत शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए संसद में कानून पारित कर आर.टी.ई. लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से छूट प्रदान की जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

आज अपराह्न १ बजे बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पर धरना–प्रदर्शन कर पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से छूट देने की मांग उठाई। ज्ञापन में शिक्षकों ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जबकि इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा गया था। शिक्षकों का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के १ सितम्बर २०२५ के निर्णय के बाद अब देश के सभी राज्यों में अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने

होली पर ३ मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित, २८ फरवरी शनिवार को खुले रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय और बैंक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग ने होली पर्व के अवसर पर ३ मार्च २०२६ (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह अवकाश **Negotiable Instruments Act**, १८८१ के अधीन घोषित किया गया है। गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या ६७१/तीन– २०२५–३६(२)/२०१६ दिनांक १७ नवम्बर २०२५ के तहत वर्ष २०२६ के राजपत्रित अवकाशों की सूची में २ मार्च २०२६ को होलिका दहन तथा ४ मार्च २०२६ को होली का अवकाश पहले से घोषित था। अब शासन ने होली के पावन अवसर को देखते हुए ३ मार्च २०२६ को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित कर दिया है। हालांकि, अतिरिक्त अवकाश के कारण कार्य व्यवस्था संतुलित रखने के लिए शासन ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन अनुभाग की २७ फरवरी २०२६ की विज्ञप्ति के अनुसार २८ फरवरी २०२६ (शनिवार) को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक एवं कोषागार सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। अर्थात् जहां एक ओर होली के अवसर पर २, ३ और ४ मार्च को अवकाश रहेगा, वहीं इसकी भरपाई के रूप में २८ फरवरी (शनिवार) को नियमित कार्य दिवस घोषित किया गया है। शासन के इस निर्णय से कर्मचारियों एवं आमजन को अग्रिम रूप से कार्य व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिल गई है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

शादी के बाद पहली बार साथ दिखे वजय देवरकोंडा और रश्मिका उदयपुर में रॉयल ब्राइड के देसी लुक ने जीता दिल

मुम्बई। साउथ सिनेमा के चहेते सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना २६ फरवरी को एक बेहद खूबसूरत और पारंपरिक समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। अपनी 'ड्रीमी वेडिंग' के बाद यह जोड़ा पहली बार राजस्थान के लेक सिटी, उदयपुर के एयरपोर्ट पर देखा गया। शादी के बाद जब यह जोड़ा एयरपोर्ट पहुंचा, तो रश्मिका लाल रंग के खूबसूरत इंडियन सूट में नजर आईं, वहीं विजय ने एक स्टाइलिश इंडो–वेस्टर्न आउटफिट चुना था। पैपराजी और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। शादी के मुख्य समारोह के लिए दोनों ने डिजाइनर अनामिका खन्ना के आउटफिट्स पहने थे। रश्मिका मंदाना ने गहरे जंग और लाल रंग के बॉर्डर वाली एक भारी साड़ी पहनी थी, जो उन्हें एक रॉयल ब्राइडल लुक दे रही थी। विजय देवरकोंडा ने पारंपरिक हाथीदांत (आइवरी) रंग की धोती और उसके साथ सिंदूरी रंग का अंगवस्त्रम पहना था, जो उन्हें एक हटकर और सांस्कृतिक लुक दे रहा था। इस शादी की सबसे खास बात विजय और रश्मिका द्वारा पहने गए पारंपरिक दक्षिण भारतीय गहने थे। विजय ने परंपरा को निभाते हुए भारी सोने के हार पहने, जिनमें सिक्कों वाला 'कसु माला' और एक लंबा 'हरम' शामिल था। उन्होंने कमर पर 'ओडियानम' (सोने की बेल्ट) और कानों में 'कडुक्कन' (झुमके) भी पहने थे। पैरों में उन्होंने 'कोलुसु' (पायल) पहनी थी। रश्मिका की चोटी में लगे सोने के गहनों को 'जड़ा बिल्ला' कहा जाता है। उन्होंने अपनी साड़ी के साथ 'शोल्डर ज्वेलरी' (कंधों की चेन), भारी मांग टीका और कई परतों वाले सोने के हार पहने थे, जो उन्हें एक शाही दुल्हन का रूप दे रहे थे। खबरों के मुताबिक, इस नवविवाहित जोड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को हैदराबाद में होने वाले अपने भव्य वेडिंग रिसेप्शन के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

अल्लू सिरिश और नयनिका रेड्डी की शादी का आधिकारिक ऐलान! ६ मार्च को लेंगे सात फेरे, जानें प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की डिटेल्स

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक, अल्लू परिवार में शादी का जश्न शुरू हो चुका है। 'बडी' फिल्म के अभिनेता अल्लू सिरिश ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपनी मंगेतर नयनिका रेड्डी के साथ शादी की तारीखों की घोषणा की। २ मार्च, २०२६ को 'अल्लू स्टूडियो' में तेलुगु फिल्म उद्योग के सितारों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ६ मार्च, २०२६ को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में दोनों परिणय सूत्र में बंधेंगे। अपने ग पोस्ट में, तेलुगु एक्टर अल्लू सिरीश ने बताया कि नयनिका रेड्डी के साथ उनकी शादी में करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। यह कपल २ मार्च, २०२६ को अल्लू स्टूडियो में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स के लिए प्री–वेडिंग सेलिब्रेशन भी होस्ट करेगा। अपने **X** हैंडल पर उन्होंने लिखा, 'नयनिका और मैं ६ मार्च को परिवार और दोस्तों के साथ एक छोटी सी शादी कर रहे हैं। हम २ मार्च को अल्लू स्टूडियो में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपने प्री–वेडिंग सेलिब्रेशन को बड़े ही शानदार तरीके से मनाने के लिए एक्साइटेड हैं।' इससे पहले, कपल ने दुबई में प्री–वेडिंग सेलिब्रेशन होस्ट किया था, जिसमें उनके भाई, पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन और दूसरे करीबी दोस्त शामिल हुए थे। जिन्हें पता हो, अल्लू सिरीश की मंगेतर, नयनिका रेड्डी, हैदराबाद की एक बिजनेस फैमिली से हैं और इंस्टाग्राम पर उनके १६.७K फॉलोअर्स हैं। अल्लू सिरीश और नयनिका रेड्डी ने अक्टूबर २०२५ में सगाई की थी। बडी एक्टर अल्लू सिरीश ने सगाई सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट करके फैंस के साथ यह खबर शेयर की। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, 'मैं आखिरकार और खुशी–खुशी अपनी जिंदगी के प्यार, नयनिका से सगाई कर रहा हूँ!' प्रोफेशनल फ्रंट पर, अल्लू सिरीश आखिरी बार २०२४ की एक्शन एडवेंचर फिल्म, बडी में गायत्री भारद्वाज के साथ दिखे थे। वह एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें गजनी (२००८), ओक्का क्षणम (२०१७) और बडी (२०२४) के लिए जाना जाता है।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक